



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 140]

नई दिल्ली, सोमवार, मई 19, 2014/वैशाख 29, 1936

No. 140]

NEW DELHI, MONDAY, MAY 19, 2014/VAISAKHA 29, 1936

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

अधिसूचना

मुम्बई, 13 मई, 2014

सं. टीएमपी/13/2009-वीपीटी.—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 48, 49 और 50 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण एतद्द्वारा संलग्न आदेशानुसार, विशाखापत्तनम पत्तन न्यास के मौजूदा दरमान की वैधता को विस्तारित करता है।

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

मामला सं. टीएमपी/13/2009-वीपीटी

विशाखापत्तनम पत्तन न्यास

आवेदक

कोरम :

- (i) श्री टी.एस. बालासुब्रह्मण्यन, सदस्य (वित्त)
- (ii) श्री चन्द्र भान सिंह, सदस्य (अर्थशास्त्र)

आदेश

(अप्रैल 2014 के 4थें दिन पारित)

यह मामला विशाखापत्तनम पत्तन न्यास (वीपीटी) के मौजूदा दरमान की वैधता के विस्तार से संबंधित है।

2. वीपीटी का मौजूदा दरमान (एसओआर) इस प्राधिकरण द्वारा पिछली बार आदेश सं. टीएमपी/13/2009-वीपीटी, दिनांक 18 फरवरी, 2011, जिसे 31 मार्च, 2011 को भारत के राजपत्र में अधिसूचित किया गया था, द्वारा अनुमोदित किया गया था। यह आदेश दरमान की वैधता 31 मार्च, 2013 तक निर्धारित करता है। यह प्राधिकरण वीपीटी के दरमान की वैधता दो बार विस्तारित कर चुका है। इस प्राधिकरण ने पिछली बार वीपीटी के मौजूदा दरमान की वैधता अपने आदेश दिनांक 10 जनवरी, 2014 द्वारा 31 मार्च, 2014 तक विस्तारित की थी।

3.1. वीपीटी द्वारा अपने पत्रों दिनांक 8 फरवरी, 2013 और 22 मार्च, 2013 द्वारा दाखिल किए गए प्रस्ताव पर संबद्ध उपयोक्ताओं/उपयोक्ता एसोसिएशन के साथ विचार-विमर्श किया गया है। हमारे पत्र दिनांक 8 अगस्त, 2013 द्वारा वीपीटी से मांगी गई अतिरिक्त सूचना/स्पष्टीकरण 19 नवम्बर, 2013 को भेजा गया है। इस प्रस्ताव पर संयुक्त सुनवाई 20 सितम्बर, 2013 को आयोजित की गई थी।

3.2. तत्पश्चात्, वीपीटी ने अपने पत्र दिनांक 18 दिसम्बर, 2013 द्वारा उल्लेख किया था कि बीओटी प्रचालक के साथ रियायत अनुबंध पर हस्ताक्षर होने के अद्यतन विकास के मद्देनजर, उसके प्रस्ताव में यातयात, आय अनुमानों और घाटा अनुमानों में बदलाव किया जा सकता है। इसके सामान्य संशोधन प्रस्ताव पर प्रभाव रखते हुए वीपीटी द्वारा बताई गई उपर्युक्त स्थिति के मद्देनजर, वीपीटी को हमारे पत्र दिनांक 31 दिसम्बर, 2013 द्वारा अपना प्रस्ताव

अद्यतन करने और 7 जनवरी, 2014 तक जमा करने की सलाह दी गई थी। वीपीटी से अपना संशोधित प्रस्ताव दाखिल करने के लिए 20 फरवरी, 2014 तक और विस्तार दिया गया था। अतः, वीपीटी को उसका संशोधित प्रस्ताव दाखिल करने के लिए 20 फरवरी, 2014 तक का समय स्वीकृत किया गया था।

3.3. बाद में, वीपीटी ने अपने पत्र दिनांक 2 अप्रैल, 2014 द्वारा उद्धरित किया कि वित्तीय वर्ष 2013-14 समाप्त हो चुका है, वर्ष 2013-14 के लिए वास्तविक यातायात, आय और व्यय के साथ 2013-14 के अनुमानों को अद्यतन करते हुए अपना संशोधित प्रस्ताव दाखिल करने के लिए 30 जून, 2014 तक का समय मांगा था। इसने मौजूदा दरमान की वैधता को 30 जून, 2014 अथवा दरमान को अंतिम रूप दिए जाने की तारीख तक, जो भी पहले हो, विस्तारित करने का अनुरोध किया था। वीपीटी द्वारा किए गए निवेदनों के मद्देनजर, पत्तन को 2013-14 के वास्तविकताओं से अद्यतन करते हुए अपना संशोधित प्रस्ताव दाखिल करने के लिए 30 जून, 2014 तक समय दिया गया है। वीपीटी को यह भी सूचित किया गया है कि उसे संशोधित प्रस्ताव दाखिल करने के लिए और समय विस्तार नहीं दिया जाएगा।

4. पत्तन से संशोधित अद्यतन किया गया प्रस्ताव प्राप्त होने पर आंतरिक जांच की जाएगी और, यदि जरूरी हो तो, संबद्ध अंशधारकों के साथ विचार-विमर्श किया जाएगा। उसके मद्देनजर, इस मामले को अंतिम रूप देने में कुछ और समय लगेगा।

5. वीपीटी के मौजूदा दरमान की वैधता 31 मार्च, 2014 को समाप्त हो चुकी है। अपना संशोधित अद्यतन किया गया प्रस्ताव दाखिल करने के लिए वीपीटी द्वारा मांगे गए समय पर विचार करते हुए, यह प्राधिकरण इसकी समाप्ति की तारीख से 30 जून, 2014 तक वीपीटी के मौजूदा दरमान की वैधता को विस्तारित करता है।

6. यदि स्वीकार्य लागत और स्वीकार्य प्रतिलाभ से अधिक कोई अतिरिक्त अधिशेष 1 अप्रैल, 2013 के बाद की अवधि के लिए प्रकट होता है तो इसके कार्यनिष्पादन की समीक्षा के दौरान, ऐसा अतिरिक्त अधिशेष निर्धारित किए जाने वाले प्रशुल्क में पूर्णतः समायोजित किया जाएगा।

टी.एस. बालासुब्रह्मण्यन, सदस्य (वित्त)

[विज्ञापन III/4/असा./143/2014]

TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS NOTIFICATION

Mumbai, the 13th May, 2014

No. TAMP/13/2009-VPT.—In exercise of the powers conferred under Sections 48, 49 and 50 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Tariff Authority for Major Ports hereby extends the validity of the existing Scale of Rates of the Visakhapatnam Port Trust as in the Order appended hereto.

TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS Case No.TAMP/13/2009-VPT

The Visakhapatnam Port Trust

- - -

Applicant

QUORUM

- (i) Shri T.S. Balasubramanian, Member (Finance)
- (ii) Shri Chandra Bhan Singh, Member (Economic)

ORDER

(Passed on this 4th day of April, 2014)

This order relates to the extension of the validity of the existing Scale of Rates of the Visakhapatnam Port Trust (VPT).

2. The existing Scale of Rates (SOR) of the VPT was last approved by this Authority *vide* Order No.TAMP/13/2009-VPT dated 18 February, 2011 which was notified in the Gazette of India on 31 March, 2011. The Order prescribes the validity of the SOR till 31 March, 2013. This Authority has extended the validity of SOR of VPT on couple of occasions. This Authority has last extended the validity of the existing SOR of VPT till 31 March, 2014 *vide* its Order dated 10 January, 2014.

3.1. The proposal filed by the VPT *vide* its letters dated 8 February, 2013 along with its letter dated 22 March, 2013 has been taken on consultation with the concerned users/user associations. The additional information/clarification sought from the VPT *vide* our letter dated 8 August, 2013 has been furnished by the port on 19 November, 2013. Joint hearing on the proposal was held on 20 September, 2013.

3.2. Subsequently, the VPT *vide* its letter dated 18 December, 2013 has stated that in view of latest development of signing of Concession Agreement with BOT operator, the traffic, income estimates and deficit estimates, in its proposal may undergo a change. In view of the above position brought out by the VPT having an impact on its general revision proposal, the VPT was advised *vide* our letter dated 31 December, 2013 to update its proposal and submit it by 7 January, 2014. The VPT requested for further extension up to 20 February, 2014 to file its revised proposal. The VPT, therefore, was allowed time up to 20 February, 2014 to file its revised proposal.

3.3. The VPT has subsequently, *vide* its letter dated 2 April, 2014 citing that the financial year 2013-14 is over, sought time up to 30 June, 2014 to file its revised proposal updating the estimates of 2013-14 with actual traffic, income and expenditure for 2013-14. It has also requested to extend the validity of the existing SOR till 30 June, 2014

or till the date of finalization of SOR, whichever is earlier. In view of the submissions made by the VPT, the port has been granted time till 30 June 2014 to file its revised proposal updating with 2013-14 actuals. The VPT has also been informed that no further extension of time will be granted to file its revised proposal.

4. The revised updated proposal when received from the port will have to be examined internally and, if necessary, involve consultation with the concerned stakeholders. In view of that, it will take some more time for finalization of the case.

5. The validity of the existing SOR of the VPT has expired on 31 March, 2014. Considering the time sought by the VPT to file its revised updated proposal, this Authority extends the validity of the existing SOR of the VPT from the date of its expiry till 30 June, 2014.

6. If any additional surplus over and above the admissible cost and permissible return emerges for the period post 1 April, 2013, during the review of its performance, such additional surplus will be set off fully in the tariff to be determined.

T.S. BALASUBRAMANIAN, Member (Finance)

[ADVT. III/4/Exty./143/2014]